EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 1, Issue 1, July-December, 2012, Available online at: www.eduzonejournal.com

भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के रूप में

सुनीता[1], रोचना मित्तल[2]

शोधार्थीनी, एस० डी० (पी०जी०) कॉलेज, गाज़ियाबाद

Corresponding Author: Sunita: ravindersahdev1972@gmail.com

शोध सार

आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की सर्वाधिक लोकप्रिय संसदात्मक व्यवस्था के लिए जितना राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है उतना ही संसदात्मक सरकार की सफलता के लिए सशक्त विरोधी दल की उपस्थिति आवश्यक है । शक्तिशाली विरोधी दल के अभाव में जनहित की अवेहलना होती है और यह हमारा दुर्भाग्य है कि भारत में लंबे समय तक सशक्त व शक्तिशाली विपक्ष का निर्माण नहीं हो सका ।

आपातकाल के दौरान कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने एक बार घोषणाकी थी , 'देश बिना विपक्ष के चल सकता है भारत के इतिहास में विपक्ष अप्रसांगिक है । ' यह सत्य है कि भारत में एक सशक्त व शक्तिशाली विपक्ष का हमेशा अभाव रहा लेकिन यह कहना कि वह अप्रसांगिक है सत्तारूढ़ सरकार को अधिनायक वादी व निरंकुश होने का मौका देने की प्रवृत्ति लगती है ।

भारतीय दलीय व्स्था अपने प्रारंभिक 40 वर्षों तक एक ध्रुवीय रही है जहां प्रतिपक्ष की आवाज़ सुनाई तो देती थी लेकिन सत्तारूढ़ सरकार के प्रभाव के नीचे दब जाती थी वर्तमान में भारत की दलीय व्यवस्था दो ध्रुव के रूप में प्रकट होने लगी है जहां एक और कांग्रेस व दूसरी ओर भाजपा है।यह सत्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस सारे देश में निर्विरोध सत्ता की अधिकारी बन गई इसके बावजूद अनेक गैर कांग्रेसी दल सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए मौजूद थे ।

भारतीय जन संघ कांग्रेस सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति अपनायी गयी नीतियों से ना खुश थी उसने सरकार से मांग की कि वह अपनी नीतियों में परिवर्तन कर पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाए और जम्मू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लिया जाए ।आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में भारतीय जनसंघ ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई और राष्ट्रीय हित में जनता पार्टी के साथ अपना विलय कर लिया परंतु शीघ्र ही जनसंघ का जनता पार्टी से निष्कासन कर दिया गया और भारतीय जनसंघ जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा के रूप में पुनः जीवित हो गया । भाजपा ने अपनी राजनीतिक यात्रा में लंबी प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह जिम्मेदारी के साथ किया । इस शोध पत्र में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है।

परिचय

प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्वरूप एवं उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है इसके अभाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता संदिग्ध होती है ।भारत में राजनीति के पटल पर अनेक दल विद्यमान है किंतु यहां स्वस्थ दलीय व्यवस्था का भाव रहा है इसमें कोई संदेह नहीं की वैध सरकार की स्थापना में राजनीतिक दलों के प्रति लगाव तथा प्रतिबद्धता एक अनिवार्य शर्तें है मुनरो के अनुसार ' 'स्वतंत्र राजनीतिक दल ही लोकतंत्रीय सरकार का दूसरा नाम है ' हमारे संविधान में संसदीय लोकतंत्र की सफलता हेतु दलीय व्यवस्था व राजनीतिक दलों की प्रवृत्ति का उल्लेख नहीं किया गया जो अति आवश्यक था । इस व्यवस्था के अभाव में स्वाधीनता के बाद भारत में जो दलीय व्यवस्था सामने आई वह भारत की संसदात्मक व्यवस्था की सफलता के लिए कार्य कारगर सिद्ध नहीं हो सकी । यहा जो भी दल गठित हुए वेजाती, धर्म, कुलीन तंत्र,समाज में क्षेत्रीय तत्वों पर गठित रहे फलत: दलों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि ये न केवल प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है बल्कि संसदीय व्यवस्था की सफलता में भी बाधक बनने लगी हैं

इतना ही नहीं संसदीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक ये राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह करने में भी आंशिक सफलता ही प्राप्त कर सके। इसका सर्वप्रथम कारण यह है कि कांग्रेस दल ने चार दशकों तक भारतीय व्यवस्था पर अपना वर्चस्व बनाए रखा और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पद्धति को दिशा निर्देश प्रदान किया किंतु दुखद पहलू यह रहा कि इस दल ने अपने भीतरी संगठन में लोकतांत्रिक पद्धति की प्रक्रिया को सुदृढ़ नहीं होने दिया और न अन्य दलों हेतु कोई आदर्श मानक प्रस्तुत कर सकी। सत्ताधारी दल अन्य दलों को विभ्रम की स्थिति में जाने को विवश करता रहा और यदि ये दल विकल्प बनाने का प्रयास करते तो सत्ताधारी दल उन्हें संरक्षण देता ताकि वे केवल दबावकरी समूह के रूप में ही कार्य कर सके । सच यह है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं विभिन्न मतों और विचारों का संगठन है जिसने विपक्षी दलों की भूमिका को स्वयं मे ही समा लिया जिसके परिणाम स्वरुप सशक्त विपक्ष का निर्माण न हो सका ।इसके बावजूद अनेक गैर कांग्रेसी या विरोधी दल कांग्रेसी सरकार पर नियंत्रण के लिए मौजूद थे । इन विरोधी आवाज में एक आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थीजो नेहरू व कांग्रेस सरकार की नीतियों व शासन व्यवस्था से नाराज थे । भारतीय जनसंघ कांग्रेस सरकार द्वारा पाकिस्तान के प्रति अपनायी गयी नीतियों से ना खुश थी उसने सरकार से मांग की कि वह अपनी नीतियों में परिवर्तन कर पाकिस्तान के प्रति कड़ा रुख अपनाये और जम्मू कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ से वापस ले लिया जाए । कांग्रेस सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को विशेष महत्व दिया, जमीदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाए परंतु इन सब नीतियों को जिस प्रकार से लागू किया गया उसे से जनसाधारण को विशेष लाभ न होकर पूर्व स्थापित सम्पत्तिशाली और मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ। सरकार के सहकारी खेती के कार्यक्रम पर प्रतिपक्ष दल जनसंघ का कहना था कि **"यह अनुभव सिद्ध है की खेती में भारी मशीनों के उपयोग ने बेकरी की समस्या को जन्म दिया है देश में ऐसी प्रणाली लागू करना जिससे विकास की स्वतंत्रता समाप्त हो जाए, प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाए और बेकारी की समस्या ओर भी भीषण हो जाए देश हित की दृष्टि से तबाही का रास्ता है"**।

आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की बहाली के लिए जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाए गए आंदोलन में भारतीय जनसंघ ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई और राष्ट्रीय हित में जनता पार्टी के साथ अपना विलय कर दिया परंतु दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर जनसंघ का जनता पार्टी से निष्कासन कर दिया गयाऔर भारतीय जन संघ जनता पार्टी से अलग होकर भाजपा के रूप में पुनः जीवित हो गया ।भाजपा ने अपनी राजनीतिक यात्रा में लंबी प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह जिम्मेदारी के साथ किया है । राजीव सरकार के समय पंजाब में कानून और व्यवस्था की समस्याएं गंभीर थी ,इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरकारी मशीनरी की अनुमति से 3000 से अधिक सिखों को अपनी जान गंवानी पड़ी और सिखों के इस नरसंहार के लिए किसी को दंड नहीं मिला । भाजपा ने पंजाब में कानून व्यवस्था के सुधार के लिए सत्याग्रह भी किया। सरकार भ्रष्टाचार ,मुद्रास्फीति , बेरोजगारी व सांप्रदायिक सौहार्द इत्यादि का समाधान करने में असफल रही । बोफोर्स प्रकरण सरकार के आर्थिक कदाचार का उदाहरण बन गया । नरसिम्हा सरकार के विरुद्ध भाजपा ने जिम्मेदारी से अपना प्रतिपक्ष कर्तव्य निभाया ।

सदैव लाइसेंस परमिट कोटा राज का विरोध करते हुए भाजपा ने सिद्धांत के रूप में उदारीकरण की नीति का स्वागत किया ।उसने आरक्षण के मुद्दे पर दूरदर्शिता दिखाई और आर्थिक सिद्धांत के आधार पर आरक्षण को स्वीकार किया लेकिन वह फोर्स मुद्दे को उसने जोर शोर से संसद में उठाया। उसका मानना था की सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए ।सरकार ने उदारीकरण और भूमंडलीकरण की नीति को स्वीकार किया जबकि भाजपा ने इसके विरोध में नारे बुलंद किये परंतु बीजेपी राव सरकार के जिस भूमंडलीकरण क विरुद्ध नारा लगा रही थी सत्ता में आने के बाद वह स्वयं इस नीति पर चलने लगी। 6 वर्ष केंद्र में सत्तारूढ़ रहने के बाद पिछले दो लोकसभा चुनाव के परिणाम स्वरुप भाजपा संसद में विपक्ष के उत्तरदायित्व व जिम्मेदारी को निभा रही है। उसने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना ही नहीं की बल्कि सरकार की उचित नीतियो व कार्यवाहियों पर उसकी प्रशंसा भी की और भारतीय जनता के समक्ष कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपनी विचारधारा व सिद्धांतों के अनुरूप एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर व समृद्ध भारत और ऐसा लोकतंत्र जिसकी राजनीति का मूल धर्म में निहित हो प्रस्तुत किया लेकिन सरकार में आने के बाद भाजपा ने गठबंधन धर्म के नाम पर क्या किया यह जग जाहिर है।

सितंबर 2006 को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यू० पी० ए० सरकार की कमियों को उजागर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार किसी भी मुद्दे पर ईमानदार साबित नहीं हो रही है मुद्दा महंगाई का हो, आतंकवाद का हो,पाठक समिति की रिपोर्ट का हो किसानों की आत्महत्या का हो,न्यूक्लियर डील का हो,अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण काहो या फिर बेरोजगारी का हो। महंगाई से त्रस्त आम नागरिकों की लड़ाई को भाजपा ने संसद से लेकर सड़कों तक लड़ी है। भाजपा युवा मोर्चा ने आतंकवाद का विरोध देश भर में मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। यू०पी०ए०सरकार आज उस आम आदमी का विश्वास खोती जा रही है जिसके भीतर ढेरो आशाएं जगाकर वह दोबारा दिल्ली का सिंहासन पाने में कामयाब हुई थी । ए० राजा और शशि थरूर के मामले में मंत्रीय भ्रष्टाचार उजागर हुआ और इन मुद्दों पर भाजपा को लोकप्रिय आवाज बनने का अवसर प्राप्त हुआ ।

लोकसभा में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री अरुण जेटली द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य में वर्तमान सरकार के बजट सत्र को प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा एक अवसर के रूप मेंस्वीकार किया गया इसके द्वारा उन्होंने यू०पी०ए०सरकार की आवश्यक वस्तुओं (विशेष कर खाद्य वस्तुओं) के बढ़ते हुए दामों को नियंत्रित करने की अक्षमता से आहत हुए लोगों के बारे में जानकारी दी। बजट में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों अर्थात तेल की कीमतों में वृद्धि के साथ शुल्कों में बढ़ोतरी,सेवा कर में लगातार वृद्धि से व बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने की असफलता से यूपीए सरकार की अयोग्यता सिद्ध हुई। टेलीफोन टैपिंग प्राइवेसी के अधिकार का जोकि वैयक्तिक स्वतंत्रता का मूल तत्व है अवमूल्यन करता है। समूचे प्रतिपक्ष ने लोकतन्त्रीय मानकों की इस घोर अवज्ञा को लेकर सरकार की आलोचना की ।इस सत्र में मूल्यवृद्धि ,भ्रष्टाचार ,सीबीआई का अवमूल्यन ,टेलीफोन टैपिंग के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के अवमूल्यन पर अधिक फोकस रहा ।देश के विपक्ष ने कांग्रेसनीत यू ०पी०ए सरकार पर लगे तमाम आरोपो के लिए सरकार को संसद में अनेक बार घेरा है पर यूपीएस सरकार का यह कहना कि विपक्षियों का तो काम है आरोप लगाना गलत है भारत में प्रति द्वंदात्मक प्रजातंत्र है जिसमें विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ताकि मुद्दों पर जनता को शिक्षित किया जा सके और सत्तारूढ़ सरकार को तानाशाही होने से रोका जा सके ।

ऐसा भी नहीं है कि भाजपा पूरी तरह पाक साफ राजनीतिक पार्टी है राज्य गठबंधन के रूप में सत्तारूढ़ होने के बाद उसने जो कार्य किये वो पूरी तरह उचित और कारगर नहीं थे । वाजपेयी सरकार ने उस अमेरिकी ऊर्जा कंपनी एनरान को मंजूरी दी जिसके शीर्ष अधिकारी भ्रष्टाचार के दल दल में फसे हुए थे । पेट्रोलियम मंत्री राम नाइक ने अपने बंधु - बांधवों को खुले हाथ से पेट्रोल पंप बाटे। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में पकड़े गए सांसदों में सबसे ज्यादा भाजपा के थे और फिर भाजपा कांग्रेस की विरोधी पार्टी नहीं अपितु सत्ता हथियाने के मामले में उसकी प्रतियोगी पार्टी है ।विपक्ष में रहते हुए वह कांग्रेस पर जो भी आरोप लगाते हैं सत्ता में आने के बाद वे उनमें से किसी की भी बात करने या जांच करने की स्थिति में नहीं होते ।स्मरणीय है कि कांग्रेस के बाद जब-जब जहां जहां भाजपा सत्ता में आई वहां आज तक पूर्व सत्ता नशीनो में से किसी को भी सत्ता पाने के पूर्व लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई सजा नहीं दिला सकी है ।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है किभारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक यात्रा में लंबी प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वाह पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया है ।उसने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों की आलोचना ही नहीं की बल्कि सरकार की उचित नितियों व कार्यवाहियों पर उसकी प्रशंसा भी की और भारतीय जनता के समक्ष कांग्रेस के विकल्प के रूप में अपनी विचारधारा व सिद्धांतों के अनुरूप एक स्वतंत्र , आत्मनिर्भर , समृद्ध भारत और ऐसा लोकतंत्र जिसकी राजनीति का मूल धर्म मे निहित हो प्रस्तुत किया फिर भी कुछ राजनीति समीक्षाको का यह भी मानना है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भाजपा सांसद के भीतर और बाहर प्रभावी भूमिका निभाने में विफल है इसका एक कारण यह हो सकता है कि जो कार्य भाजपा को करना चाहिए था वह

कांग्रेस के ही कुछ नेता करते नजर आ रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपने कुछ नेताओं को भाजपा से विपक्ष की भूमिका हड़प लेने के लिए होशियारी से छूट दे रखी हो ।दूसरे भाजपा को जब भी विपक्षी तेवर दिखाने का मौका मिला उसने या तो देर से उन अवसरों को पहचाना या कमजोर आवाज में अपनी बात कही जिसका कारण पार्टी का आंतरिक कलह और आपसी सामंजस्य की कमी है अगर विपक्ष प्रभावी न हो तो उसका असर लोकतंत्र की क्वालिटी पर पड़ता है अतः भाजपा को आपसी कलह व असामंजस्य को छोड़कर भारतीय जनता के हित में कार्य करना चाहिए ।

संदर्भिका

[1] रजनी कोठारी भारत में राजनीतिक पृष्ठ 34 से 35
[2] भारतीय जनता पार्टी का संविधान एवं नियम,2008
[3] 'कार्यकारी दल की रिपोर्ट 1985' –भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005 नीति दस्तावेज।
[4] 'कार्यकारी दल की रिपोर्ट 1985'- भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005 नीति दस्तावेज खंड 4।
[5] आहूजा, गुरदास. भारतीय राजनीति और भाजपा का आगमन प्रकाशक राम कंपनी नई दिल्ली-17
[6] आडवाणी, लालकृष्ण."मेरा देश मेरा जीवन" प्रभात प्रकाशन,4/19 आसफ अली रोड नई दिल्ली-110002
[7] देशमुख, नाना जी."राजनीतिक दुर्भावना के शिकार" राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचारों तब विचार उत्तेजक अध्ययन।
[8] हेगड़ी दंतोपंत, एकात्म मानववाद-एक अध्ययन, राजधर्म पुस्तक प्रकाशन लखनऊ।
[9] हेगड़ी दंतोपंत, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, विचारदर्शन, सुरुचि प्रकाशन, झंडेवाला।
[10] मलकानी के०आर० प्रसाद, जगदीश. जनसंघ से भाजपा विचारधारा के बढ़ते चरण, प्रकाशक भाजपा केंद्रीय कार्यालय, 11, अशोका रोड, नई दिल्ली-110001
[11] पद्मिनी, हरिश्चंद्र डॉक्टर, डॉ० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, समकालीन दृष्टि में, प्रकाशक, नोएडा न्यूज़ प्रा० ली०48, श्रधानंद मार्ग, दिल्ली-110006
[12] सिन्हा सच्चिदानंद,"भारत का राजनीतिक संकट" ।
[13] उपाध्याय, दीनदयाल."भारतीय राजनीतिक विकास की एक दिशा" लोकहित प्रकाशन लखनऊ।
[14] उपाध्याय, दीनदयाल."भारतीय अर्थनीति: विकास की एक दिशा, लोकहित प्रकाशन, लखनऊ।
[15] वाजपेयी, अटल बिहारी. कुछ लेख कुछ भाषण।
[16] वाजपेयी, अटल बिहारी. राजनीति की रपतीली राहें।
[17] भारतीय जन संघ 1951 से 1975,"अध्यक्षीय भाषण" प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोका रोड नई दिल्ली-110001
[18] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005, चुनाव घोषणा पत्र खंड-1, प्रकाशक भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001

[19] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"अध्यक्षीय भाषण" भाग-1, खंड-2 प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001

[20] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"अध्यक्षीय भाषण" भाग-2, खंड-3 प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक कारण नई दिल्ली-110001

[21] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"नीति दस्तावेज" खंड-4, प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001

[22] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"राजनितिकप्रस्ताव" खंड-5, प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001

[23] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"आर्थिक प्रस्ताव" खंड-6, प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001

[24] भारतीय जनता पार्टी 1980 से 2005,"अन्यप्रस्ताव" खंड-7, प्रकाशक, भारतीय जनता पार्टी 11 अशोक का रोड नई दिल्ली-110001